होना चाहिए कि दो घंटे तक जब बिजली नहीं हो और सैकड़ों यात्री वहां पर भटक रहे हों, एयर इंडिया की फ्लाईट नं० 112 वहां पर आए, पहले अमेरिकन एक फ्लाईट आई, जाल की फ्लाईट आई और ऐसे में एयरपोर्ट अथारिटी का एक भी अधिकारी वहां पर नही था, इससे बढ़ कर गंभीर मामला और कोई नहीं हो सकता है। इससे देश की बेजती होती है, पर्यटन को धक्का पहुंचता है और एयर इंडिया का भी कार्य इन दिनों बहुत असंतोषजनक चल रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Shri Ram Awadhesh Singh not here, Shri Jagdish Prasad Mathur not here. Shri Sarada Mohanty.

Insufficient Teaching Staff in the Rural Kendriya Vidyalayas of the Country

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa) : Sir, my Special Mention is regarding insufficient teaching staff in the rural Kendriya Vidyalayas of the country. In order to facilitate children of transferable Central Government servants and Defence personnel, to have an equal standard of education at every place, the Central Government established Kendriya Vidyalayas throughout the country and abroad. But I am sorry to say that Kendriya Vidyalayas in the rural areas have not been provided with sufficient teaching staff as compared with that of the metros. It will be seen that metro Vidyalayas have surplus teaching staff. The students of rural Kendriya Vidyalayas are not able to finish their courses of study before their examinations as the Vidyalayas are lacking in teaching staff in some subjects. So these students are debarred from competing with the students of the metros. Teachers who are not specialised in a subject are teaching the subject in addition to the subject in which they have specialised. So the standard of teaching is deteriorating day by day. It is learnt that 6,000 vacancies of teaching staff have remained unfilled. No advertisement for recruitment has been made during the preceding two years. In this regard, the AIKVTA representatives, guardians, MPs and others have made several requests to the higher authorities but no fruitful step has yet been taken.

As regards transfer of the teaching staff and others in Kendriya Vidyalayas, sanctity has been thrown to winds. There are many irregularities in the case of transfers. About a thousand transfers have been ordered in total disregard of the KVS Official Transfer Policy. Teachers are manipulating their transfer to the places they want. Teachers of the metros are also manipulating to remain at one place for decades.

It has appeared in the "Sunday Observer" recently that in Kendriya Vidyalayas an "Advance Booking of Transfer System" has also been introduced.

In order to avoid the difficulties being faced by the students of rural K.Vs., the required teaching staff in each subject should be provided before the academic year begins and irregularities in transfer orders should be avoided.

Hence I urge upon the hon. Minister for Human Resource Development and also the hon. Prime Minister to look into the matter at an early date so that the Kendriya Vidyalayas of rural areas get sufficient teaching staff before the academic year begins and to do away with all kinds of irregularities regarding transfer and posting of teaching staff in the Kendriya Vidyalayas. Thank you, Sir.

Reported Advice given by SHO, Lajpat Nagar, New Delhi to Girl Victimised for dowry to turn to call Girl Trade

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में सरकार का ध्यान बहुत ही गंभीर व शर्मनाक घटना की ओर अपने इस विशेष उल्लेख द्वारा दिलाना चाहती हूं यह जघन्य घटना मैं सिर्फ इसलिए ही नहीं बताना चाहती कि यह पूनम नाम की लड़की

[श्रीमती वीणा वर्मा]

के शोषण या उत्पीड़न की है बल्कि यह घटना एक ऐसी मजबूर लड़की की है जिसको देह व्यापार में धकेलने वाला खुद एक सब-इंस्पेक्टर है जिसका कि प्रमाण वह टेप-रिकार्डेड कनवर्सेसन है जो कि नेशनल कमीशन फार वूमेन की चैयर पर्सन श्रीमती जयन्ती पटनायक, जोकि एक भूतपूर्व संसद सदस्य भी है, की उपस्थिति में उस सब-इंस्पेक्टर के साथ उस महिला की बातचीत है। यह टेप नेशनल वूमेंस कमीशन की अध्यक्ष के पास है। वह इसे हमारे गृह मंत्री जी माननीय जैकब साहब के पास भी ले गयी थीं। इस संबंध में श्रीमती जयंती पटनायक और इंडियन हाउस वाइफ एसोसिएशन की सचिव श्रीमति संध्या शर्मा गृह मंत्री श्री जैकब साहब से मिली है और उन्हें तुरंत कार्यवाही करने के लिए कहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह घटना कुछ इस तरह से है कि 24 वर्षीय श्रीमती पूनम बालूजा नाम की लड़की जिसकी कि 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी अपने पति से पिटते-पिटते तंग आकर पति से अलग होकर चादरें बेचने का काम कर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, लेकिन फिर भी उसके पति की मार व अत्याचार कम नहीं हुए। इसकी शिकायत उसने क्राइम अगेंस्ट वूमेन सेल में की लाजपत नगर (दक्षिणी) पुलिस थाने में सात बार शिकायत करने व चार महीने बीतने भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उल्टे नतीजा यह हुआ कि पूनम के पति ने पुलिस के साथ मिलकर पूनम पर झूठा केस बनाकर 10 अप्रैल को उसको अरेस्ट कराया। पूनम को दोपहर भर थाने में बिठाए रखा और रात को उसको अकेली लॉक-अप में बन्द कर दिया। दोपहर से पूनम भूखी-प्यासी बैठी रही और रात भर उसको लॉक-अप में बन्द रखा गया। घर की चाबियां भी उसके पास थीं। लॉक-अप से उसे किसी को फोन करके यह नहीं कहने दिया कि उसको यहां बंद कर दिया गया है उसके दो बच्चे तीन साल और चार साल के, रात भर सड़क पर रहे। उसको किसी वकील से भी बात करने की इजाजत नहीं दी गई। पूनम रात भर अपने बच्चों के ध्यान में और भूखी-प्यासी तड़फती रही। दूसरे दिन 11 तारीख को 11 बजे उसको छोड़ा गया अफसोस की बात यह है कि वहां पर लोक-अप में उसके लिए कोई लेडी-पुलिस नहीं थी, उसको टायलेट खुले में जाने के लिए मजबूर किया गया। जब उसको दूसरे दिन छोड़ा गया तो वहां के एस. आई., जिनका नाम मैं यहां रिकार्ड कराना चाहती हूं निर्मल सिंह, उन्होंने कहा-"अब तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया है। तुम्हारा यही इलाज था तुम्हें समझाने का यही तरीका था।" लॉक-अप में उसके साथ और भी अभद्र व्यवहार किया गया जेवरात भी उतार लिए गए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 13 अप्रैल को लाजपत नगर थाने में एस. आई. के खिलाफ जब वह शिकायत लिखाने गई तो उसकी शिकायत नहीं लिखी डी. एस. पी. ने उसको दूसरे दिन बुलाया दूसरे दिन वह अपने साथ कुछ टेप वगैहर ले गई और उसकी वहां जो बात चीत हुई वह उसने रिकार्ड कर ली। उससे कहा, निर्मल सिंह जो एस. आई, है उन्होंने कहा-"यह चादर बेचने का धंधा क्यों करती हो तुम ? मैं तुमको और आसान तरीका बता सकता हूं, जिससे काफी पैसा कमाया जा सकता है।" और बहुत अश्लील बातचीत हुई, जिसको मैं यहां नहीं कह सकती हूं उसने अपनी नोटबुक निकालकर कुछ एड्रेसेस और फोन नंबर उसको बताए, जब पूनम ने पूछा कि काम क्या करना होगा ? तो उसने कहा कि काम कुछ नहीं है, कुछ बड़े होटलों में जाना होगा और लोगों से मिलना होगा। इस तरह से एक बहुत ही जघन्य अपराध में, अफसोस की बात यह है कि पुलिस स्वयं औरत को जाने पर मजबूर करती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 23 तारीख तक इस घटना पर कोई कार्यवाई नहीं हुई, तब फिर वीमेन कमीशन की चेयरमैन श्रीमती जयन्ती पटनायक उस घटना के लिए खुद गई अपना

वेश बदल कर । वहां पर उन्होंने बात रिकार्ड की । वह टेप रिकार्डर ले गयी थीं, जिससे कि बातचीत, उसके साथ हुए अभद्र व्यवहार और जो उसको कहा गया था वह रिकार्ड कर सके । लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । अफसोस यह है कि नेशनल कमीशन ओन वीमेन जो बना है, न तो उसको कोई पावर है और न किसी शिकायत पर एक्शन लिया जाता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : This is a matter for the Home Minister to look into.

श्रीमति वीणा वर्मा : जब किसी महिला की आबरु उतरती है तो क्यों बार-बार उसको कहा जाता है कि वह प्रमाण दे ? क्या नेशनल कमीशन ओन वीमेन की चेयर-परसन खुद जाए तब ही एक महिला की एफ आई आर. दर्ज की जाएगी ? क्या साधारण औरत को कोई न्याय नहीं मिलेगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में सरकार से कुछ साफ-साफ मांग करूंगी जिन पर सरकार ध्यान दे । गृह-मंत्रालय तुरन्त इस मामले में हस्तक्षेप करे । उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए लाजपत नगर, साऊथ दिल्ली के पुलिस सब-इंस्पेक्टर को फौरन मुअत्तिल करके जेल भेजा जाए । इस बात की पूरी जांच की जाए कि इस संभ्रांत महिला की दरखास्त पर पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने एक्शन क्यों नहीं लिया और पूनम के खिलाफ झूठा मुकदमा कैसे दर्ज किया ? उसको हवालत में डालकर दुर्व्यव्यहार क्यों किया गया ? इस मामले की भी पूरी जांच होनी चाहिए कि पुलिस आफीसर इस प्रकार कैसे औरतों की संभ्रांत महिलाओं की इज्जत बचाने के बजाए उन्हें देह-व्यापार में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं ? इस बात की भी उच्च स्तरीय जांच हो कि दिल्ली में ऐसे कितने पुलिस आफिसर हैं, जो कि देह व्यापार बढ़वाने में सीधे शामिल हैं ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है । इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अपराधी जो स्वय पुलिस आफिसर है, उनको उचित सजा मिलनी चाहिए । मामले की गंभीरता को देखते हुए, विशेषकर इसमें एक पुलिस आफीसर का देह-व्यापार बढ़ाने में सीधा हाथ है, मेरी सदन के द्वारा सरकार से मांग है कि शीघ्रातिशीघ्र इस विषय पर गृह मंत्री जी एक विस्तृत वक्तव्य दें कि पूरे मामले में सरकार क्या कर रही है, सदन को सूचित करें ? वे सदन को यह भी बताएं कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, विशेषकर के पुलिस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? हर सरकार, हर समाज, हर व्यवस्था महिलाओं पर होते अत्याचार और शोषण कम करने के वायदे करती है, लेकिन देखा गया है कि जब कोई घटना होती है तो न उसकी मदद के लिए पुलिस होती है और न समाज होता है, न सरकार होती है । औरत सिर्फ अकेली खड़ी है । मैं चेयर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कार्रवाई की जाए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : This incident is surely distressing. I am sure that the whole House shares the distress.

एक माननीय सदस्य : मैं भी अपने को इससे एसोसिएट करता हूं और यह चाहता हूं कि पूरा सदन, जो बैठा है ..... (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय मैं भी अपने को इससे संबद्ध करता हूं और समझता हूं कि पूरा सदन, जो माननीय सदस्यों ने कहा है, उससे सब लोग सहमत होंगे ।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : महिला पुलिस थाने बहुत कम हैं, देश के हर जगह में होने चाहिएं जहां मामले दर्ज हों महिलाओं के । हम लोग इसका समर्थन करते हैं ।

SHRI N.E. BALARAM (Kerala) : I also associate myself.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : It is a very distressing incident. I feel this brings

[SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR]

shame to our civilised system. Madam Minister, you are here and representing the Government. You must communicate to the Home Ministry that they must come out with a statement.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA-DEVI SIDDHARTHA) : Yes, Sir.

Reported Statement of the Chief Minister of Uttar Pradesh, Regarding the Federal Structure of the Country

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा संघीय ढांचे के विरुद्ध खुले विद्रोह तथा संविधान का खुला उल्लंघन करने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

महोदय, भारत के संविधान में उद्देशिका में, प्रिएम्बल में लिखा है कि :–

> "हम लोग भारत को एक (सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न, समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य) बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।"

संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ऐसी व्यवस्था भी की गई है और जब हमारे संविधान का इस तरह से संघीय ढांचा है तो उसके आधार पर हमारा दायित्व भी है कि अपने उस संविधान की और राष्ट्रीय एकता व अखंडता की रक्षा करने के लिए हम लोग प्रयास करें। इस संविधान के अंतर्गत केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है । सरकार का दायित्व है, प्रदेश सरकार का भी, कि समय-समय पर केन्द्र और राज्य का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए यदि कभी भी केन्द्र से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका सही ढंग से उत्तर देने का काम भी प्रदेश सरकार का होना चाहिए । इसी कड़ी में महोदय, यह राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का विवाद जो चल रहा है, इस सिलसिले में वहां पर जिस तरीके से सरकार के बनने के बाद से जिस तरीके से जमीन अधिग्रहित की गई है और फिर पर्यटन विभाग द्वारा सारा काम शुरू हुआ, वहां पर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट को काम सौंपा गया, तीन-तीन, चार-चार मंदिर भी ढाए गए, संकट मोचन मंदिर भी ढाया गया, उसके साथ-साथ हनुमान जी की मूर्ति भी तोड़ी गई और जबर्दस्ती महन्त को वहां से हटाने की कार्रवाई हुई और दूसरे एक महन्त बदले गए, उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि यथास्थिति बहाल की जाए, इस आदेश का भी खुला उल्लंघन हुआ है । इस तरह से जब सारी स्थिति हुई तो राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य और लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्य भी वहां की वस्तुस्थिति की जानकारी करने के लिए गए थे और इस संबंध में कई प्रश्न ऐसे आए जिनके बारे में कि माननीय गृह मंत्री जी ने प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था कि बिना उसके सही मायने में वहां की तस्वीर नहीं रखी जा सकती थी । लेकिन 22 तारीख को वहां के मुख्य मंत्री ने साफ कहा कि हम केन्द्र सरकार को किसी भी सवाल का उत्तर नहीं देंगे । 20 अप्रैल को भी जो पत्र भेजा गया था, उसके जवाब में कहा कि हम उत्तर नहीं देंगे और उसके पहले भी 13 अप्रैल को भी पत्र आया था, उसके लिए भी कह दिया कि हमें कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । इस तरह से प्रदेश सरकार जानबूझ करके उस संघीय ढांचे के विरुद्ध आचरण कर रही है और ऐसा आचरण कर रही है जिससे कि ऐसा लगता है कि वह जानबूझ करके केन्द्र से टकराहट मोल लेना चाहती है और ऐसी स्थिति में महोदय, मैं आपसे कहना चाहता